[2012] 7 एस.सी.आर. 1148

राजस्थान राज्य और अन्य

बनाम

आंजनेय आर्गेनिक हर्बल पीवीटी. लिमिटेड

(2012 की सिविल अपील संख्या 6741-6742)

सितम्बर 20, 2012

[के.एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे.जे.]

राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955.

धारा 42(बी) - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए लाभकारी कानून - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की उनकी संपूर्ण हिस्सेदारी या उसके हिस्से की बिक्री, उपहार और वसीयत पर सामान्य प्रतिबंध - उद्देश्य और इसका प्रभाव - माना गया: ऐसे सामान्य प्रतिबंधों का कारण न केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, बल्कि यह भी देखना है कि गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उनका शोषण नहीं किया जा रहा है। - हालाँकि, कभी-कभी, धारा 42(बी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों के खिलाफ भी जा सकती है - ऐसी कई स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ वे बेटे/बेटी की शादी जैसे उद्देश्यों के लिए संपत्ति बेचने का इरादा रखते हैं या बेहतर संपत्ति आदि खरीदें, लेकिन बेहतर प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं मिल सकता है, अगर बिक्री केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच की जाती है - कुछ कानूनों में प्रावधान किए गए हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को बेचने में सक्षम बनाते हैं। गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि, निर्धारित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने पर - ऐसा प्रावधान कभी-कभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, बशर्ते कि यह हो। राजस्थान किरायेदारी अधिनियम में उचित प्रावधान शामिल करने के लिए विधायिका।

धारा 42(बी) - अनुसूचित जाति के सदस्य से अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य कानूनी व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण - वैधता - धारा 42 (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' - का अर्थ - प्रतिवादी-निजी कंपनी द्वारा खरीदी गई संपत्ति अनुसूचित जाति के सदस्य - धारा 42 (बी) के मद्देनजर शून्य के रूप में चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी-निजी कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है, अनुसूचित जाति के एक सदस्य द्वारा एक न्यायिक व्यक्ति को की गई बिक्री, जिसका कोई अधिकार नहीं है जाति, धारा 42 से प्रभावित नहीं है - आयोजित। उच्च न्यायालय का तर्क निराधार है और प्रावधान की गलत व्याख्या करता है - धारा 42(बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति हो सकता है, न्यायिक व्यक्ति नहीं, अन्यथा, उस धारा का संपूर्ण उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। पराजित होना - विधायिका स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति से बचना चाहती थी जहां प्रतिवादी-कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जमीन खरीद सकती है और फिर इसे गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बेच सकती है - जो काम सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, उसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता - वैधानिक प्रतिबंध तक पहुँचना - प्रतिवादी द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों से खरीदी गई संपत्ति धारा 42 (बी) के तहत प्रभावित होने के कारण शून्य थी और इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में उत्परिवर्तन से इनकार कर दिया गया था - इसलिए, राज्य भूमि पर फिर से कब्ज़ा कर सकता है और भूमि को मूल मालिकों को लौटाएं जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं - सामान्य खंड अधिनियम, 1897 - धारा 3(42) - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 341 और 342।

प्रतिवादी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसने 26.9.2005 के एक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित भूमि खरीदी। संपत्ति के उत्परिवर्तन के लिए राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसे 19.11.2005 के एक परिपत्र के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उत्परिवर्तन केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब स्थानांतरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच हो, जैसा भी मामला हो। चूँकि उत्परिवर्तन के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की जिसे एकल न्यायाधीश ने अनुमति दे दी।

इससे व्यथित होकर, राज्य ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया।

त्वरित अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या राजस्थान काश्तकारी की धारा 42(बी) के प्रावधानों के मद्देनजर अनुसूचित जाति के सदस्य से अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य कानूनी व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण शून्य है। अधिनियम, 1955.

प्रतिवादी-कंपनी ने दलील दी कि अभिव्यक्ति 'व्यक्ति', राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 में परिभाषित नहीं है और इसलिए, किसी को सामान्य खंड अधिनियम, 1987 के तहत 'व्यक्ति' की परिभाषा के अनुसार जाना होगा, और, यदि ऐसा है तो सामान्य धारा अधिनियम की धारा 3(42) के साथ पढ़ें, तो राजस्थान किरायेदारी अधिनियम की धारा 42 के खंड (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में भी आती है और इसलिए, यदि कोई सदस्य है अनुसूचित जाति अपनी संपत्ति किसी न्यायिक व्यक्ति को बेचती है, बिक्री को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानूनी व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि कोई भी सामान्य धारा अधिनियम की धारा 3(42) को राजस्थान किरायेदारी अधिनियम की धारा 42(बी) में संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ सकता है; और यह कि राजस्थान किरायेदारी अधिनियम की धारा 42 (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' एक प्राकृतिक व्यक्ति है, न कि न्यायिक व्यक्ति और यदि स्थानांतरण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो नहीं है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तो ऐसा स्थानांतरण राजस्थान किरायेदारी अधिनियम की धारा 42 के तहत शून्य है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

आयोजित: 1.1. राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 एक लाभकारी कानून है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों की रक्षा का विशेष ध्यान रखता है। धारा 42 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की संपूर्ण हिस्सेदारी या उसके कुछ हिस्से की बिक्री, उपहार और वसीयत पर कुछ सामान्य प्रतिबंध प्रदान करती है। ऐसे सामान्य प्रतिबंधों का कारण न केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, बल्कि यह भी देखना है कि गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उनका शोषण नहीं किया जा रहा है। [पैरा 8]

1.2. संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आदि के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 342 'अनुसूचित जनजातियों' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 42 (बी) में पाए गए 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' अभिव्यक्ति को संवैधानिक प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और, यदि पढ़ा जाए, तो अभिव्यक्ति 'जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है' या अनुसूचित जनजाति' का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार सार्वजनिक अधिसूचना में शामिल किए गए लोगों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होगा। इसलिए अधिनियम की धारा 42 (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' केवल प्राकृतिक हो सकती है व्यक्ति और न्यायिक व्यक्ति नहीं, अन्यथा, उस धारा का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। यदि प्रतिवादी-कंपनी का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भूमि खरीद सकती है और फिर उसे गैर-अनुसूचित जाति को बेच सकती है। और अनुसूचित जनजाति, एक ऐसी स्थिति जिससे विधायिका बचना चाहती थी। जो चीज़ सीधे तौर पर नहीं की जा सकती, उसे वैधानिक प्रतिबंध से आगे बढ़कर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। [पैरा 12, 13 और 14]

1.3. उच्च न्यायालय का यह तर्क कि प्रतिवादी एक न्यायिक व्यक्ति है, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे न्यायिक व्यक्ति को की गई बिक्री, जिसकी कोई जाति नहीं है, अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत नहीं आती है, अस्वीकार्य है और एक देता है उपर्युक्त प्रावधान की गलत व्याख्या। राजस्व अधिकारियों ने परिपत्र दिनांक 9.11.2005 के अनुसार उत्परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया। परिपत्र की शर्त संख्या 7(2) को राजस्व अधिकारियों द्वारा उत्परिवर्तन से इनकार करने में सही ढंग से लागू किया गया था। उपरोक्त उल्लिखित शर्त यह स्पष्ट करती है कि पंजीकरण के आधार पर उत्परिवर्तन केवल उस व्यक्ति/विक्रेता विशेष के नाम पर किया जाएगा जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, न कि किसी फर्म/सोसायटी/के नाम पर। कंपनी/कानूनी संस्था जिसमें कोई व्यक्ति पदाधिकारी या सदस्य है। जब उपरोक्त सिद्धांतों को विचाराधीन भूमि के हस्तांतरण पर लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि 26.9.2005 को किया गया विक्रय विलेख शून्य था और इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में उत्परिवर्तन से इनकार करना उचित था। इसलिए प्रतिवादी द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों से दिनांक 26.9.2005 के विक्रय विलेख और अन्य विक्रय विलेखों के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति, अधिनियम की धारा 42 (बी) के अंतर्गत आने के बाद से शून्य है और इसे इस प्रकार घोषित किया गया है। इसलिए, राज्य भूमि पर पुनः कब्ज़ा कर सकता है और भूमि को मूल मालिकों को लौटा सकता है जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। [पैरा 15, 16 और 17]

महाराष्ट्र राज्य बनाम इंडियन क्विल कॉर्पोरेशन **(2004) 5 डब्ल्यूएलसी (राज.) 703 - संदर्भित।**

2. हालाँकि, कभी-कभी, राजस्थान किरायेदारी अधिनियम की धारा 42(बी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों के विरुद्ध भी जा सकती है। ऐसी कई स्थितियां हो सकती हैं जहां वे बेटे/बेटी की शादी या बेहतर संपत्ति खरीदने आदि जैसे उद्देश्यों के लिए संपत्ति बेचने का इरादा रखते हैं, लेकिन उस स्थिति में कभी-कभी उन्हें बेहतर प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं मिल सकता है, अगर बिक्री केवल की जाती है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच। ऐसे कानून देखे गए हैं जहां निर्धारित प्राधिकारी से अनुमति मिलने पर गैर-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपनी जमीन बेचने में सक्षम बनाने के प्रावधान किए गए हैं। ऐसा प्रावधान कभी-कभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सहायक हो सकता है। अनुसूचित जनजाति को उनकी भूमि की बेहतर कीमत मिले, लेकिन राजस्थान अधिनियम में उचित प्रावधान शामिल करना विधायिका का काम है। [पैरा 18]

केस लॉ संदर्भ:

(2004) 5 डब्ल्यूएलसी (राज.) 703 पैरा 4 में संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की सिविल अपील संख्या 6741-6742।

2008 की डीबी सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 896 में राजस्थान के उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 26.09.2008 से।

सी.ए. के साथ 2012 की संख्या 6743।

डॉ। अपीलकर्ताओं के लिए मनीष सिंघवी, एएजी, इरशाद अहमद।

पी.पी. चौधरी, राजेश के. भारद्वाज, डॉ. विपिन गुप्ता उत्तरवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

के.एस. राधाकृष्णन, जे. 1. अनुमति दी गयी।

2. इस मामले में, हमें इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है कि क्या धारा 42 के प्रावधानों के मद्देनजर, अनुसूचित जाति के सदस्य से अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य कानूनी व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण शून्य है। बी) राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम')।

3. राजस्थान के उच्च न्यायालय ने कई मामलों में उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि इस तरह के स्थानांतरण पर उपर्युक्त प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' एक 'न्यायिक व्यक्ति' में नहीं होगी और वह न्यायिक व्यक्ति करता है उनकी कोई जाति नहीं है और इसलिए, अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी स्थानांतरण अधिनियम की धारा 42 (बी) के अंतर्गत नहीं आएगा।

4. आक्षेपित निर्णय में, राजस्थान राज्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2004 (5) डब्ल्यूएलसी (राज.) 703 में राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया गया है, जो इस प्रकार है:

> "6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यद्यपि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक न्यायिक व्यक्ति है, लेकिन इसकी कोई जाति नहीं है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पक्ष में बिक्री धारा 42 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है। राजस्थान किरायेदारी अधिनियम। इस प्रकार तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमें लगता है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां 480 दिनों की देरी को माफ किया जाना चाहिए। विशेष अवकाश अस्वीकार कर दिया गया है।

5. जेओसी (सुप्रा) में फैसले को राजस्थान राज्य द्वारा सी.सी. में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। 2798 दिनों की देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ 2010 का नंबर 19386। इस न्यायालय ने दिनांक 4.1.2011 के आदेश के तहत याचिका को लागत सहित खारिज कर दिया, क्योंकि देरी को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया था।

6. हमें सूचित किया गया है कि चूंकि सीसी संख्या 19386/2010 से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी, आईओसी (सुप्रा) में निर्णय को जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है, कानून के रूप में माना जाता है और विभिन्न मामलों में इसका पालन किया जा रहा है। इसी तरह के

अन्य मामले. इसलिए, हमारे सामने उठाए गए विभिन्न कानूनी मुद्दों की जांच करना आवश्यक है ताकि हमारे सामने रखे गए प्रश्न पर एक आधिकारिक घोषणा की जा सके।

7. प्रतिवादी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17.8.2005 के तहत पंजीकृत है। कंपनी ने राजस्थान के जेतासन तहसील के ग्राम जेतासन पटवार क्षेत्र में स्थित खसरा नंबर 840/651 में 25 बीघे जमीन खरीदी, जिसमें से 9.73 बीघे जमीन अनुसूचित जाति के सदस्यों की थी। वह संपत्ति 26.9.2005 को एक पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा 60,000/- रुपये में खरीदी गई थी। संपत्ति के उत्परिवर्तन के लिए राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। 19.11.2005 के एक परिपत्र पर भरोसा करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उत्परिवर्तन केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब स्थानांतरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच हो, जैसा भी मामला हो। चूंकि उत्परिवर्तन के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए प्रतिवादी ने एस.बी. दायर किया। सिविल रिट याचिका संख्या 169/2006, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर, राज्य ने डी.बी. होने के नाते डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की। सिविल रिट विशेष अपील (रिट) संख्या डीआर (जे) 1177/2008, जिसे /ओसी (सुप्रा) में फैसले के बाद खारिज कर दिया गया था।

8. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह सुनी गई। यह अधिनियम एक लाभकारी कानून है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों की रक्षा का विशेष ध्यान रखता है। धारा 42 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की संपूर्ण हिस्सेदारी या उसके कुछ हिस्से की बिक्री, उपहार और वसीयत पर कुछ सामान्य प्रतिबंध प्रदान करती है। ऐसे सामान्य प्रतिबंधों का कारण न केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, बल्कि यह भी देखना है कि गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उनका शोषण नहीं किया जा रहा है। धारा 42(बी) के प्रासंगिक प्रावधान आसान संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

"42. बिक्री, उपहार और वसीयत पर सामान्य प्रतिबंध - किसी खातेदार किरायेदार द्वारा उसकी संपूर्ण हिस्सेदारी या उसके हिस्से की बिक्री, उपहार या वसीयत शून्य होगी यदि

(ए) xxxxxxx हटा दिया गया

(बी) ऐसी बिक्री, उपहार या वसीयत किसी अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की जाती है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, या किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में होती है जो सदस्य नहीं है अनुसूचित जनजाति का।"

9. श्री पी.पी. प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील चौधरी ने कहा कि 'व्यक्ति' शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए, हमें सामान्य खंड अधिनियम, 1987 के तहत 'व्यक्ति' की परिभाषा के अनुसार चलना होगा। सामान्य खंड अधिनियम 'व्यक्ति' अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"3(42)। 'व्यक्ति' में कोई भी कंपनी या निकाय या व्यक्तियों का संघ शामिल होगा, चाहे निगमित हो या नहीं।"

10. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि, यदि इसे सामान्य धारा अधिनियम की धारा 3(42) के साथ पढ़ा जाता है, तो अधिनियम की धारा 42 के खंड (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' एक न्यायिक क्षेत्र में आती है। व्यक्ति भी और इसलिए, यदि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य अपनी संपत्ति किसी कानूनी व्यक्ति को बेचता है, तो बिक्री को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानूनी व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती है।

11. दूसरी ओर, राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने तर्क दिया कि हम सामान्य धारा अधिनियम की धारा 3(42) को अधिनियम की धारा 42(बी) में नहीं पढ़ सकते हैं। प्रसंग। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 42 (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "व्यक्ति" एक प्राकृतिक व्यक्ति है, न कि न्यायिक व्यक्ति और यदि स्थानांतरण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो सदस्य नहीं है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो ऐसा स्थानांतरण अधिनियम की धारा 42 के तहत शून्य है।

12. संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आदि के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा। संविधान इस प्रकार पढ़ता है:

> "341. अनुसूचित जातियाँ- (1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जातियों, नस्लों या जनजातियों या उनके कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। ऐसी जातियाँ, नस्लें या जनजातियाँ जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियाँ मानी जाएंगी, जैसा भी मामला हो।
>
> (2) संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति के हिस्से या समूह को शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है, लेकिन पूर्वोक्त को छोड़कर उक्त खंड के तहत जारी की गई अधिसूचना किसी भी बाद की अधिसूचना से भिन्न नहीं होगी।

13. संविधान का अनुच्छेद 342 'अनुसूचित जनजातियों' से संबंधित है और इस प्रकार है:

"342. अनुसूचित जनजातियाँ - (1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या आदिवासी समुदायों या उनके कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे, जैसा भी मामला हो।

(2) संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय के हिस्से या समूह को शामिल या बाहर कर सकती है, लेकिन उपरोक्त अधिसूचना को छोड़कर उक्त खंड के तहत जारी किए गए किसी भी बाद की अधिसूचना में बदलाव नहीं किया जाएगा। "

14. 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' अभिव्यक्ति, जो हम अधिनियम की धारा 42 (बी) में पाते हैं, को संवैधानिक प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और, यदि पढ़ा जाए, तो अभिव्यक्ति 'जो इसका सदस्य नहीं है' अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार सार्वजनिक अधिसूचना में शामिल किए गए लोगों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होगा। इसलिए अधिनियम की धारा 42(बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति हो सकता है, न्यायिक व्यक्ति नहीं, अन्यथा, उस धारा का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। यदि कंपनी का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जमीन खरीद सकती है और फिर उसे गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बेच सकती है, ऐसी स्थिति से विधायिका बचना चाहती थी। जो बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जा सकती, उसे वैधानिक प्रतिबंध से आगे बढ़कर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता।

15. इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का यह तर्क कि प्रतिवादी एक न्यायिक व्यक्ति है, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे न्यायिक व्यक्ति को की गई बिक्री, जिसकी कोई जाति नहीं है, प्रभावित नहीं होती है अधिनियम की धारा 42, अस्थिर है और उपर्युक्त प्रावधान की गलत व्याख्या करती है।

16. हमारा यह भी मानना है कि राजस्व अधिकारियों ने दिनांक 9.11.2005 के परिपत्र के अनुसार उत्परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया। परिपत्र की शर्त संख्या 7(2) को राजस्व अधिकारियों द्वारा उत्परिवर्तन से इनकार करने में सही ढंग से लागू किया गया था, जो शर्त आसान संदर्भ के लिए नीचे दी गई है:

> "7(2). यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का खातेदार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्ति को विक्रय करता है जो किसी फर्म/सोसाइटी/कंपनी/ईगल संस्था का पदाधिकारी है, तो नामांतरण के आधार पर पंजीकरण केवल उस विशिष्ट व्यक्ति/प्रतिनिधि के नाम पर किया जाएगा जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, न कि उस फर्म/समाज/कंपनी/कानूनी संस्थान के नाम पर जिसमें वह पदाधिकारी या सदस्य है।

17. उपरोक्त उल्लिखित शर्त यह स्पष्ट करती है कि पंजीकरण के आधार पर उत्परिवर्तन केवल उस व्यक्ति/विक्रेता विशेष के नाम पर किया जाएगा जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, न कि किसी फर्म/के नाम पर। सोसायटी/कंपनी/कानूनी संस्था जिसमें कोई व्यक्ति पदाधिकारी या सदस्य है। जब हम उपरोक्त सिद्धांतों को भूमि के हस्तांतरण के लिए लागू करते हैं, तो हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 26/9/2005 को किया गया विक्रय पत्र अमान्य था और इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में उत्परिवर्तन से इनकार करना उचित है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों से विक्रय विलेख दिनांक 26/9/2005 और अन्य विक्रय विलेखों के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति, अधिनियम की धारा 42 (बी) के अंतर्गत आने के बाद से शून्य है और इसे इस प्रकार घोषित किया गया है। इसलिए, राज्य भूमि पर पुनः कब्ज़ा कर सकता है और भूमि को मूल मालिकों को लौटा सकता है जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

18. हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि कभी-कभी धारा 42(बी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों के खिलाफ भी जा सकती है। ऐसी कई स्थितियां हो

सकती हैं जहां वे बेटे/बेटी की शादी या बेहतर संपत्ति खरीदने आदि जैसे उद्देश्यों के लिए संपत्ति बेचने का इरादा रखते हैं, लेकिन उस स्थिति में कभी-कभी उन्हें बेहतर प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं मिल सकता है, अगर बिक्री केवल की जाती है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच। हमने ऐसे कानून देखे हैं जहां निर्धारित प्राधिकारी से अनुमति मिलने पर गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपनी जमीन बेचने में सक्षम बनाने के प्रावधान किए गए हैं। ऐसा प्रावधान कभी-कभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि की बेहतर कीमत पाने में सहायक हो सकता है लेकिन राजस्थान अधिनियम में उचित प्रावधान शामिल करना विधायिका का काम है।

19. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.बी.बी. अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।